(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1990-91 के लिए आरम्भ में राज्य व्यापार निगम का निर्यात लक्ष्य 1050 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लक्ष्य में गाद में कमी कर दी गयी थी; यदि हां, तो इसमें कितनी कमी की गयी थी ; और

(घ) उक्त निर्यात लक्ष्य में किन कारणों से कमी करनी पड़ी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। लक्ष्य में 580 करोड़ रुपये के स्तर तक कमी कर दी गयी थी।

(घ) एस.टी.सी. द्वारा निर्यात कम करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :—

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन और कुछ मदों का गैर-सरणीकरण ;

(ख) पूर्वी यूरोप का बाजार खुलने में परिवर्तन होने की वजह से जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य तथा अन्य देशों को चमड़े के निर्यात की धीमी गति ;

(ग) मसाला व्यापार निगम को मसाले का तथा एम.एम.टी.सी./पी.ई.सी. को कुछ इंजीनीयरी मदों का निर्यात सौंपा जाना ;

(घ) टी.टी.सी आई. द्वारा एस.टी.सी. की मार्फत चाय का निर्यात अपेक्षानुसार न होना ;

(ङ) ईराक से बंगलादेश को सीमेंट के निर्यात के लिए ईराकी संविदाओं का रद्द होना ;

(च) एस.टी.सी. को बजाय भारतीय व्यापारियों से प्रत्यक्ष रूप से चावल खरीदने का जी.सी.सी. का निर्णय ;

(छ) प्रति व्यापार निर्यात की कार्य विधि में परिवर्तन ।

विजाग इस्पात संयंत्र के लिए धन राशि उपलब्ध कराया जाना

1017. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई 1990 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "विजाग स्टील प्लांट रन्स इनटू रफ वेदर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आवश्यक धनराशि के अभाव में इस परियोजना को निर्धारित समानुसार पूरा नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) इस परियोजना के लिए निर्धारित की गई धनराशि को समय पर उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय का मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना को वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, इस परियोजना को पूरा किये जाने में विलम्ब के ये भी कारण हैं :—येलेरू हैं नहर के पूरा किये जाने में विलम्ब, विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से उपस्करों की सप्लाई और कुछ स्वदेशी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं का अपर्याप्त कार्य निष्पादन। पूंजीगत धन की कमी के कारण परियोजना को उसकी वित्तीय जरूरतों के लिए समय पर धन नहीं मिलता